वी. एम. जैन, न्यायाधीश की उपस्थिति में

मैसर्स विमको लिमिटेड, - याचिकाकर्ता

बनाम

होराम और अन्य, - प्रतिवादी

2003 का सीआर नंबर 261

4 नवम्बर, 2003

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 22 नियम 10 सीपीसी, याचिकाकर्ता मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति खरीदना - क्या उसे नियम 10 के तहत प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सकता है - आयोजित, नहीं- हालांकि, आदेश 22 नियम 10 के तहत वह प्रतिवादियों / विक्रेताओं की ओर से मुकदमे का बचाव करने का हकदार है।

यह निर्णय लिया गया कि आदेश 22 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के मद्देनजर भले ही याचिकाकर्ता को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, फिर भी आवेदक-याचिकाकर्ता को अपने विक्रेताओं (प्रतिवादियों) की ओर से मुकदमे का बचाव करने की अनुमति दी जा सकती है ) चूंकि आवेदक ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मुकदमे की संपत्ति खरीदी थी। मुकदमे की संपत्ति बेचने के बाद, प्रतिवादियों (आवेदक के विक्रेताओं) को मुकदमे की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी और ऐसी परिस्थितियों में, आवेदक को मुकदमे का बचाव करके अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति देना उचित होगा (विक्रेता की ओर से)। चूंकि आवेदक-याचिकाकर्ता ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मुकदमे की संपत्ति खरीदी थी और उसे अपने विक्रेताओं की ओर से मुकदमे का बचाव करने की अनुमति दी जा रही है, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आवेदक-याचिकाकर्ता एक नया लिखित बयान दाखिल करने का या प्रतिवादियों द्वारा पहले से अपनाए गए रुख के अलावा एक नया रुख अपनाने के लिए हकदार नहीं होगा।

(पैरा 5)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके जैन।

राजीव शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

**निर्णय**

वी.एम. जैन, न्यायाधीश.

1. यह पुनरीक्षण याचिका आवेदक याचिकाकर्ता मेसर्स विमको लिमिटेड द्वारा निचली अदालत द्वारा पारित 18 सितंबर, 2002 के आदेश के खिलाफ

दायर की गई है, जिसमें आवेदक द्वारा सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. होराम और महिपाल ने लाल सिंह आदि के खिलाफ घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, आवेदक-याचिकाकर्ता मेसर्स विमको लिमिटेड द्वारा आदेश 1 नियम 10, सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें इस आधार पर प्रतिवादियों में से एक के रूप में शामिल किया गया था कि आवेदक-कंपनी ने 168 कनाल 10 मरला की भूमि खरीदी थी और वर्तमान मुकदमे में शामिल भूमि उक्त भूमि का हिस्सा थी जिसे उसके द्वारा खरीदा गया था और आवेदक-कंपनी का कब्ज़ा भी था ।यह कहा गया कि भले ही वादी इस तथ्य के बारे में जानते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने आवेदक कंपनी को मुकदमे में आवश्यक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया था। यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमे में एक प्रतिवादी के रूप में आवेदक-कंपनी को शामिल करना, न्याय के हित में और मुकदमे में शामिल मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक था। वादी द्वारा जवाब दाखिल करके उक्त आवेदन का विरोध किया गया था और इसमें कहा गया कि आवेदक-कंपनी एक आवश्यक पक्ष नहीं थी क्योंकि आवेदक-कंपनी ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वाद भूमि खरीदी थी और इस प्रकार, मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता था। दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने 18 सितंबर, 2002 के आदेश के तहत आदेश 1 नियम 10, सीपीसी के तहत आवेदक-कंपनी के आवेदन को खारिज कर दिया। उसी से व्यथित, आवेदक-कंपनी ने इस न्यायालय में वर्तमान संशोधन याचिका दायर की। प्रस्ताव की सूचना जारी की गई।

3. मैंने पक्षों के वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

4. वादी-प्रतिवादियों के वकील ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने आदेश 1 नियम 10, सीपीसी के तहत आवेदक-याचिकाकर्ता के आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मुकदमा संपत्ति खरीदी थी, वह आवश्यक या उचित पक्ष नहीं था और उसे आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता था। **सरविंदर सिंह** बनाम **दलीप सिंह और अन्य** (1) पर निर्भरता रखी गई। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता कंपनी के वकील ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया कि भले ही याचिकाकर्ता को आदेश 1 नियम 10, सीपीसी के तहत प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, फिर भी याचिकाकर्ता अपने विक्रेताओं की ओर से मुकदमे का बचाव करने की अनुमति पाने का हकदार है जैसा कि आदेश 22 नियम 10, सीपीसी के तहत प्रदान किया गया है। सर्विंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान मुकदमा संपत्ति खरीदी थी, उसे आवश्यक या उचित पक्ष नहीं माना जा सकता है और उसे आदेश 1 नियम 10, सीपीसी के तहत एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के संचालन से लिस पेंडेंस के सिद्धांत से अलगाव प्रभावित हुआ था। इस प्राधिकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, विद्वान ट्रायल कोर्ट आदेश 1 नियम 10, सीपीसी के तहत आवेदक-याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने में पूरी तरह से उचित था। हालांकि, आवेदक को निश्चित रूप से अपने विक्रेताओं की ओर से मुकदमे का बचाव करने की अनुमति दी जा सकती है, खासकर जब आवेदक-याचिकाकर्ता कंपनी ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मुकदमा संपत्ति खरीदी थी, जैसा कि आदेश 22 नियम 10, सीपीसी के तहत प्रदान किया गया है, जो निम्नानुसार है। .—

> "10. **मुकदमे में अंतिम आदेश से पहले असाइनमेंट के मामले में प्रक्रिया**-(i) वाद के लंबित रहने के दौरान किसी असाइनमेंट, सृजन या किसी हित के हस्तांतरण के अन्य मामलों में, वाद न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा या उसके खिलाफ जारी रखा जा सकता है जिसे ऐसी रुचि आई है या हस्तांतरित की गई है।
>
> (1) xxx xxx xxx"

(5) ऊपर उल्लिखित सीपीसी के आदेश 22 नियम 10 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, भले ही याचिकाकर्ता को आदेश 1 नियम 10, सीपीसी के तहत प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, फिर भी आवेदक-याचिकाकर्ता को अपने विक्रेताओं (प्रतिवादियों) की ओर से मुकदमे का बचाव करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान मुकदमा संपत्ति खरीदी थी। मुकदमा संपत्ति बेचने के बाद, प्रतिवादियों (आवेदक के विक्रेताओं) को मुकदमा संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं होगी और ऐसी परिस्थितियों में, मेरी राय में, आवेदक को मुकदमे का बचाव करके (अपने विक्रेताओं की ओर से) अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति देना उचित होगा। इस संबंध में भरोसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर किया जा सकता है, **खेमचंद शंकर चौधरी और अन्य बनाम विष्णु हरि पाटिल और अन्य (2)** चूंकि आवेदक-याचिकाकर्ता ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान मुकदमा संपत्ति खरीदी थी और उसे अपने विक्रेताओं की ओर से मुकदमे का बचाव करने की अनुमति दी जा रही है, यह कहने की जरूरत नहीं है कि आवेदक याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा पहले से अपनाए गए रुख के अलावा एक नया लिखित बयान दायर करने और / या एक नया रुख अपनाने का हकदार नहीं होगा, जिन्होंने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे मुकदमा संपत्ति बेची थी।

(6) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जाती है, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 18 सितंबर, 2002 के आदेश को रद्द किया जाता है और आवेदक-याचिकाकर्ता को अपने विक्रेताओं की ओर से वाद का बचाव करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि आदेश 22 नियम 10, सीपीसी के तहत प्रदान किया गया है।

(7) चूंकि इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए पक्षकारों को अपने वकील के माध्यम से कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए 16 दिसम्बर, 2003 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

---

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी